विचार बिन्दु

सफलता का केवल एक ही रहस्य है, साधारण चीजों को असाधारण तरीके से करना। –जॉन डी. रॉकफेलर

राजस्थान: आर.जी.एच.एस. पेंशनरों को परेशानी, सरकार की उदासीनता

RGHS राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, विधायकों, पूर्व विधायकों और अन्य पात्र लाभार्थियों को नकद रहित चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना है। सितंबर 2021 में शुरू हुई यह योजना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) की तर्ज पर तैयार की गई थी। इसका लक्ष्य लगभग 13 लाख सरकारी कर्मचारियों कके परिवारों को, जिसमें 8 लाख सरकारी कर्मचारी और 3.28 लाख पेंशनर शामिल हैं, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना रहा है। योजना के तहत नकद रहित उपचार, प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का वार्षिक कवरेज (गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये), आउटडोर मरीजों (OPD) के लिए 20,000 रुपये की सीमा, और इनडोर मरीजों (IPD) के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन इसके बावजूद, पेंशनरों को इस योजना के तहत कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो इसकी उपयोगिता को कम कर रहा है। पेंशनरों की समस्याओं की लगातार अनदेखी सरकारी उदासीनता, घोटालों पर घोटालों ने इसकी विश्वसनीय को हिलाकर रख दिया है। सरकार को समस्त। जानकारी है लेकिन कोई इस पर प्रामाणिक चर्चा के लिए तैयार नहीं है । होना यह चाहिए कि योजना के परिमार्जन हेतु अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करते हुए इसे विश्वसनीय बनाया जाए। पेंशनर्स इस समाज में सरकार के अघोषित और अवैतनिक एम्बेसडर हैं सरकार की प्राथमिकता में इन्हें सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए।

पेंशनरों की समस्याएँ उप्ए के कार्यान्वयन में कई खामियों को सिद्दत से उजागर कर रही हैं। पहली और सबसे बड़ी समस्या दवाइयों की अनुपलब्धता है। पैनल में शामिल फार्मेसी स्टोर्स पर जीवन रक्षक और नियमित दवाएँ अक्सर उपलब्ध नहीं होतीं हैं। उदाहरण के लिए, बारां और कोटा जैसे जिलों में पेंशनरों ने बताया कि फार्मेसी स्टोर्स ने RGHS के तहत दवाएँ देना बंद कर दिया, क्योंकि सरकार ने उनके बकाया भुगतानों में महीनों की देरी की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, RGHS के तहत फार्मेसी स्टोर्स के 500 करोड़ रुपये से अधिक के बिल लंबित पड़े हैं। इससे पेंशनरों को निजी तौर पर दवाएँ खरीदनी पड़ रही हैं, जो उनकी सीमित पेंशन आय पर भारी बोझ डाल रहा है। कई बुजुर्ग पेंशनरों ने अपनी बचत खर्च करने या गहने बेचने की शिकायत की है, खासकर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए। दूसरी प्रमुख समस्या नकद रहित सुविधा का वास्तविकता में लागू न होना है। RGHS का दावा है कि यह योजना लाभार्थियों को सरकारी और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में नकद रहित उपचार प्रदान करती है। जबकि पेंशनरों को शिकायत की है कि अनेक अस्पताल कैशलेस सुविधा प्रदान नहीं करते और उन्हें इलाज के लिए पहले नकद भुगतान करना पड़ता है। इसके बाद प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया इतनी जटिल और समय लेने वाली है कि कई बुजुर्ग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते।

जयपुर के एक 75 वर्षीय पेंशनर ने बताया कि उनके हृदय शल्य चिकित्सा के लिए 3 लाख रुपये का बिल निजी तौर पर चुकाना पड़ा, और प्रतिपूर्ति के लिए दावा जमा करने के बावजूद भुगतान नहीं मिला। यह प्रक्रिया विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के पेंशनरों के लिए और भी कठिन है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और कागजी कार्रवाइयों से परिचित नहीं हैं उनकी हालत बहुत खराब है। वृद्धावस्था में दंत समस्या सबसे अधिक गम्भीर होती है लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दंत चिकित्सा और इससे जुड़ी अन्य सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को RGHS के दायरे से बाहर रख छोड़ा है। पेंशनरों, विशेष रूप से वृद्धों, को दंत समस्याओं जैसे रूट कैनाल, डेन्चर, या दाँतों की सफाई के लिए निजी क्लीनिकों पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार ने दंत चिकित्सा पर नाम मात्र की आपूर्ति का प्रावधान कर छोड़ा है। आज अगर एक वृद्ध व्यक्ति को यदि अपने दांतों का पूरा ढांचा लगवाना पड़े तो दो से तीन लाख रुपए खर्च करने होंगे सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा, कुछ विशेष जांचें जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, या कैंसर स्क्रीनिंग भी कई अस्पतालों में RGHS के तहत कवर नहीं होतीं। इससे पेंशनरों को अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है।

उदाहरण के लिए, एक पेंशनर ने बताया कि उनकी कैंसर स्क्रीनिंग की लागत RGHS में शामिल नहीं थी, जिसके लिए उन्हें 50,000 रुपये निजी तौर पर खर्च करने पड़े। इसी तरह पैनल में शामिल अस्पतालों की अपर्याप्त सुविधाएँ और अनावश्यक जांचें हैं। कई निजी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं जैसे पर्याप्त बेड, विशेषज्ञ डॉक्टर, या उन्नत उपकरणों की कमी है। इसके विपरीत, कुछ अस्पताल अनावश्यक जांचें और लंबे समय तक भर्ती करके RGHS फंड का दुरुपयोग करते हैं। जयपुर के एक निजी अस्पताल में एक पेंशनर को सामान्य बुखार के लिए 10 दिन तक भर्ती रखा गया और 28 जांचें की गईं, जो चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक थीं। यह न केवल पेंशनरों के लिए परेशानी का कारण बनता है, बल्कि योजना के संसाधनों का दुरुपयोग भी करता है। सरकारी अस्पतालों में भी स्थिति बेहतर नहीं है, जहाँ बेड की कमी, लंबी प्रतीक्षा अवधि, और विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपस्थिति आम समस्याएँ हैं। पेंशनर्स के प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में देरी और अस्वीकृति है जो उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण है। जब पेंशनरों को नकद भुगतान करना पड़ता है, तो वे ऑनलाइन RGHS पोर्टल के माध्यम से दावा जमा करते हैं। जिसमें अनेक मामलों में दावे तकनीकी कारणों जैसे अपूर्ण दस्तावेज या अस्पष्ट नियमों के कारण अस्वीकार कर दिए जाते हैं। 2024 में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि RGHS के तहत 30% से अधिक दावे 3-6 महीने से अधिक समय तक लंबित रहते हैं। यह देरी पेंशनरों के लिए वित्तीय तनाव का कारण बनती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले ही इलाज पर अपनी बचत खर्च कर चुके हैं। सरकारी उदासीनता ने इन समस्याओं को और गंभीर किया है। सबसे पहले, बकाया भुगतानों में देरी ने फार्मेसी स्टोर्स और अस्पतालों कों उप्ए के तहत सेवाएँ देने से हतोत्साहित किया है। 2024 तक, अनुमानित 500 करोड़ रुपये के बिल लंबित थे, जिसके कारण कई अस्पतालों ने कैशलेस सुविधा बंद कर दी। दूसरा, निगरानी तंत्र की कमी ने घोटालों को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड में 343 करोड़ रुपये का टेंडर घोटाला सामने आया, जिसमें फर्जी बिलिंग और अधिकारियों की मिलीभगत शामिल थी। तीसरा, पेंशनरों के बीच जागरूकता की कमी एक बड़ी समस्या है। कई पेंशनरों को RGHS के नियमों, पात्रता, और प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है। सरकार ने इसके लिए जागरूकता अभियानों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। चौथा, RGHS का प्रशासनिक ढांचा बार-बार बदल रहा है, जैसे कि हाल ही में वित्त विभाग से चिकित्सा विभाग को योजना हस्तांतरण की है, जिसने भ्रम और अक्षमता को बढ़ाया है। RGHS में घोटाले इस योजना की विश्वसनीयता को और कम कर रहे हैं। फर्जी बिलिंग एक प्रमुख समस्या है, जिसमें अस्पताल अनावश्यक जांचें और भर्ती करके RGHS फंड का दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक जांच में पाया गया कि जयपुर और उदयपुर के कुछ अस्पतालों ने सामान्य बीमारियों के लिए 5-10 लाख रुपये के बिल बनाए, जो चिकित्सकीय रूप से अनुचित थे। इसके अलावा, 2000 करोड़ रुपये के फर्जी बिलों का मामला सामने आया, जिसमें दवाइयों और उपकरणों के लिए फर्जी टेंडर शामिल थे। इन घोटालों में अधिकारियों, डॉक्टरों, और निजी कंपनियों की मिलीभगत की बात सामने आई है। नकली दवाएँ और फार्मेसी स्टोर्स पर जीवन रक्षक दवाओं की अनुपलब्धता ने भी पेंशनरों का विश्वास तोड़ा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, प्रशासनिक सुधार जरूरी हैं। एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया जाए, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ, पेंशनर प्रतिनिधि, और ऑडिटर शामिल हों। यह समिति नियमित रूप से अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर्स की जाँच करे। अस्पतालों और स्टोर्स को समय पर भुगतान के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाए। दूसरा, पेंशनरों की सुविधा के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, जिसमें हिंदी में सरल जानकारी उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक जिले में RGHS शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएँ, और मौजूदा हेल्पलाइन (181) को और प्रभावी बनाया जाए। दंत चिकित्सा और विशेष जांचों को RGHS के दायरे में शामिल किया जाए। तीसरा, घोटालों की रोकथाम के लिए ऑनलाइन ऑडिट सिस्टम लागू किया जाए, जिसमें AI और मशीन लर्निंग का उपयोग हो। फर्जी बिलिंग में शामिल अस्पतालों को पैनल से हटाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चौथा, RGHS पोर्टल और मोबाइल ऐप को बुजुर्गों के लिए सरल बनाया जाए, जिसमें हिंदी भाषा और वॉयस कमांड का विकल्प हो। एक डिजिटल ई-वॉलेट सिस्टम शुरू किया जाए, जिसमें पेंशनरों के चिकित्सा रिकॉर्ड और शेष राशि की जानकारी हो। इसी प्रकार अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाएँ RGHS को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं।

> **जयपुर के एक 75 वर्षीय पेंशनर ने बताया कि उनके हृदय शल्य चिकित्सा के लिए 3 लाख रुपये का बिल निजी तौर पर चुकाना पड़ा, और प्रतिपूर्ति के लिए दावा जमा करने के बावजूद भुगतान नहीं मिला। यह प्रक्रिया विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के पेंशनरों के लिए और भी कठिन है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और कागजी कार्रवाइयों से परिचित नहीं हैं उनकी हालत बहुत खराब है।**

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में देश भर में 300 से अधिक शहरों में पैनल अस्पतालों का व्यापक नेटवर्क है। RGHS को भी अन्य राज्यों में अस्पतालों का विस्तार करना चाहिए। CGHS की तरह ऑनलाइन दवा वितरण शुरू किया जाए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (CMCHIS) में ऑनलाइन दावा ट्रैकिंग और त्वरित निपटान की प्रणाली है, जिसे RGHS में लागू किया जा सकता है। तमिलनाडु का PPP मॉडल भी अस्पतालों की संख्या बढ़ाने में उपयोगी हो सकता है। केरल की करुणा स्वास्थ्य योजना में गंभीर बीमारियों के लिए विशेष कवरेज और सामुदायिक भागीदारी के उदाहरण अपनाए जा सकते हैं। दिल्ली की आयुष्मान भारत योजना में मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। स्पष्ट है कि RGHS में पेंशनरों की समस्याएँ, जैसे दवाइयों की अनुपलब्धता, नकद रहित सुविधा का अभाव, और घोटाले, इस योजना की कमजोरियों को दर्शाते हैं। सरकारी उदासीनता ने इन समस्याओं को और बढ़ाया है। प्रशासनिक सुधार, तकनीकी उन्नयन, और अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर RGHS को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यह योजना पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है, बशर्ते सरकार इन समस्याओं को गंभीरता से ले और त्वरित कदम उठाए। पेंशनर्स के प्रति सरकार का सौहार्द पूर्ण रवैया स्वयं सरकार की शाख को बढ़ाने वाला होगा। वरिष्ठ नागरिकों की हिफाजत और उनका सम्मान किसी भी समाज की संवेदनशीलता का प्रमाण होता है आशा है सरकार इस दिशा में समुचित कदम उठाएगी।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र मोहन शर्मा,
वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिन्तक

पाली जिले के लिये वरदान जवाई बांध परियोजना - जल संरक्षण की मजबूत मिसाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रदेश में जल की कमी न हो, प्रदेश हरा-भरा और स्वच्छ हो

सौरभ सिंगारिया

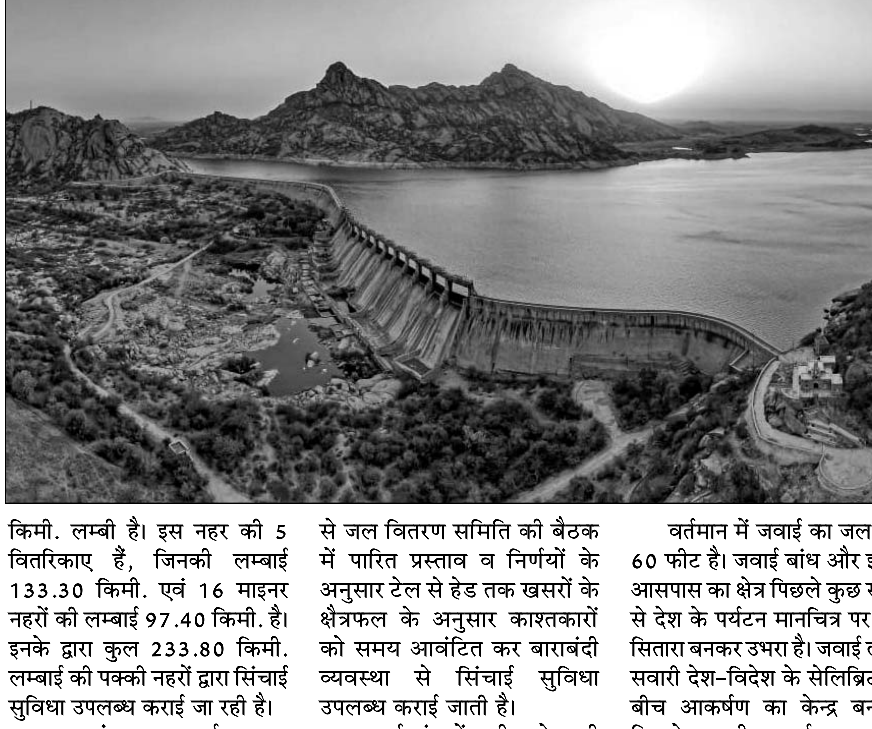

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रदेश में जल की कमी न हो, उसका संरक्षण और संग्रहण किया जाए जिससे प्रदेश खुशहाल बने, साथ ही प्रदेश में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाए जिससे कि प्रदेश हरा-भरा बने।

इसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए राज्य में ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून, 2025 से प्रारंभ किया है जिसमें जल संरक्षण संठाहण, पर्यावरण संरक्षण व पौधारोपण , स्वच्छता और इसके लिये जागरूकता को महत्व दिया है।

जवाई बांध - पाली की लाइफलाइन :- इस बाँध का शिलान्यास जोधपुर महाराजा उम्मेदसिंह द्वारा 13 मई, 1946 को किया गया था। परियोजना की कुल लागत 2.60 करोड रूपये थी। बांध निर्माण कार्य 1957 में पूर्ण हुआ। निर्माण के बाद 1973 में प्रथम बार गेट खोल कर पानी की निकासी की गई एवं बांध का गेज 60.00 फिट से बढ़ाकर 61.25 फीट किया गया।

बांध में पानी की आवक बढाने के लिये वर्ष 1969 से 1978 के मध्य सेई अपर्वतन योजना का कार्य किया गया। सेई बांध से 6776 मीटर लम्बी सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में पानी का अपर्वतन प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2006 के दौरान सेई बांध की उचाई 8.25 मीटर से बढाकर 10.93 मीटर की गई जिसमें जवाई बांध को अतिरिक्त 516 मीट्रिक घन फीट पानी उपलब्ध हो सका। निर्माण के 63 वर्षो में अब तक अब तक जवाई बांध मात्र 9 बार ही पूर्ण भरा एवं वर्ष 1973 से 2017 के बीच आठ बार जवाई बांध के गेट खोलकर पानी को जवाई नदी में छोडा गया।

पेयजल में प्रमुख स्त्रोत :- जवाई बांध से वर्तमान में सिरोही जिले के शिवगंज कस्बे एवं पाली जिले के शहरों समेत 9 कस्बों सुमेरपुर, देसूरी, रानी, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, रोहट, सोजत व बाली तथा 985 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

सिंचाई से किसानों को लाभ :- जवाई बांध से 57 गांवों के 38671.00 हैक्टेयर (पाली जिले के 33 गांव एवं जालौर जिले के 24 गांवों के 38600 किसान सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होते है।

नहरों की स्थिति :- जवाई कमाण्ड क्षेत्र में मुख्य नहर 23.10 किमी. लम्बी है। इस नहर की 5 वितरिकाए हैं, जिनकी लम्बाई 133.30 किमी. एवं 16 माइनर नहरों की लम्बाई 97.40 किमी. है। इनके द्वारा कुल 233.80 किमी. लम्बाई की पक्की नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

जल संगम :- जवाई कमाण्ड क्षेत्र में सरकार व किसानों के बीच तालमेल व सिंचाई में सरकार की ओर से पारदर्शिता के लिये किसानों के लिये 15 जल उपभोक्ता संगम है। इनके सहयोग से जल वितरण समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव व निर्णयों के अनुसार टेल से हेड तक खसरों के क्षैत्रफल के अनुसार काश्तकारों को समय आवंटित कर बाराबंदी व्यवस्था से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

जवाई बांध में पानी लाने वाली सेई बांध की सुरंग को 1.5 मीटर गहरा करने हेतु कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के बाद जवाई को 840 मीट्रिक घन फीट प्रतिवर्ष अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा।

वर्तमान में जवाई का जल स्तर 60 फीट है। जवाई बांध और इसके आसपास का क्षेत्र पिछले कुछ समय से देश के पर्यटन मानचित्र पर नया सितारा बनकर उभरा है। जवाई लेपर्ड सवारी देश-विदेश के सेलिब्रिटी के बीच आकर्षण का केन्द्र बना है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में जबर्दस्त परिवर्तन आया है।

सौरभ सिंगारिया
सहायक निदेशक, पाली
सूचना एवं जनसंपर्क
विभाग, राजस्थान

म्यूचुअल फंड्स को भी डीमैट में लाना क्यों ज़रूरी है?

सुनील दत्त गोयल

भारत में पूंजी बाजार लगातार विकसित हो रहा है। भारतीय वित्तीय बाजार में डिजिटलीकरण की क्रांति ने पिछले दशकों में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए हैं। टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और सरकार ने समय-समय पर कई दूरदर्शी निर्णय लिए हैं। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी सिक्योरिटीज को 100झ डीमैट (डिमैटेरियलाइज़्ड) फॉर्मेट में लाना ऐसा ही एक कदम था, जिसने शेयर बाजार में धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम किया और लेनदेन को त्वरित एवं पारदर्शी बनाया। सेबी और सरकार डिजिटलीकरण का ढिंढोरा तो पीटती हैं, मगर म्यूचुअल फंड्स के मामले में जानबूझकर पिछड़ापन क्यों बनाए हुए हैं? शेयरों और प्राइवेट कंपनी शेयरों को डीमैट में बदलकर उन्होंने दिखा दिया कि वे जानते हैं कि कैसे धोखाधड़ी रोकी जाती है। फिर इस 72 लाख करोड़ के एक महत्वपूर्ण निवेश के साधन म्यूचुअल फंड्स को डीमैट में अनिवार्य करने की दिशा में अब तक कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्या यह जानबूझकर की गई लापरवाही है?

देश की एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (ए एम सी) करोड़ों निवेशकों का पैसा संभालती हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मई 2025 के अंत में कुल एयूएम 72.18 लाख करोड़ था। यह पिछले महीनों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि और साल-दर-साल उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जिसमें उद्योग का एयूएम अप्रैल 2025 में 70 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर गया है।

यह बात समझ से परे है: म्यूचुअल फंड्स का वॉल्यूम आज लिस्टेड सिक्योरिटीज के वॉल्यूम के लगभग बराबर है। इसके बावजूद यह पारंपरिक और जटिल व्यवस्थाओं में फंसा हुआ है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स को 100झ डीमैट में लाने से न केवल निवेशकों का काम आसान होगा, बल्कि पूरे बाजार में क्रांतिकारी बदलाव होगा। जैसे आरबीआई हर रोज डॉलर और विदेशी मुद्राओं की दर तय करता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स की एनएवी तो रोज घोषित होती है, फिर यही यूनिट्स उसी दिन के भाव पर क्यों नहीं खरीदी-बेची जा सकतीं? क्या तकनीक नहीं है, या फिर इच्छाशक्ति की कमी है?

वर्तमान स्थिति और चुनौतियां

वर्तमान में, म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए निवेशकों के पास दो विकल्प हैं - या तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट (एसओए) के माध्यम से या फिर डीमैट अकाउंट के माध्यम से। हालांकि, डीमैट फॉर्मेट एक विकल्प मात्र है, अनिवार्य नहीं। इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे रिडेम्पशन में देरी, पेपरवर्क की अधिकता, और निवेशकों के लिए अपने पोर्टफोलियो का समग्र दृश्य प्राप्त करने में कठिनाई। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग का आकार विशाल है। मई 2025 तक, भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 72.20 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि म्यूचुअल फंड्स अब भारतीय निवेशकों के बीच कितने लोकप्रिय हो गए हैं। इतने बड़े बाजार के लिए एक समान, पारदर्शी और कुशल प्रणाली की आवश्यकता है।

डीमैट फॉर्मेट के लाभ

म्यूचुअल फंड्स को अनिवार्य रूप से डीमैट फॉर्मेट में लाने से कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे:

निवेशकों के लिए लाभ

1. रियल-टाइम ट्रांजैक्शन: निवेशक तुरंत ऑनलाइन रिडेम्पशन और खरीद कर सकेंगे, जिससे उन्हें उसी दिन का नवीनतम मूल्य मिलेगा, बिना एक दिन का इंतज़ार किए।

2. एकीकृत पोर्टफोलियो दृश्य: निवेशक अपने सभी निवेशों - शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स - को एक ही डीमैट अकाउंट में देख सकेंगे, जिससे पोर्टफोलियो प्रबंधन आसान होगा।

3. पेपरवर्क में कमी: डीमैट फॉर्मेट में म्यूचुअल फंड्स रखने से भौतिक दस्तावेजों या पेपरवर्क की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।समस्त कार्य पेपर लेस होने की वजह से माननीय मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया का सपना साकार होता है ।

बाजार के लिए लाभ

1. बाजार में वॉल्यूम वृद्धि: म्यूचुअल फंड्स को ट्रेडेबल बनाने से बाजार में वॉल्यूम में तुरंत प्रभाव से वर्तमान मूल्यांकन के हिसाब से बेहतर 72 लाख करोड रुपए से भी अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

2. रॉन्ग सेलिंग पर लगाम: एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा स्कीम की गलत बिक्री की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी।

3. ब्रोकर्स के लिए अवसर: शेयर बाजार के ब्रोकर्स के पास बड़ा वॉल्यूम आएगा, जिससे उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी।

4. डिजिटल परिवर्तन: पूरा म्यूचुअल फंड सिस्टम डिजिटल हो जाएगा, जिससे भारत के डिजिटल वित्तीय परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा।

फंड मैनेजर्स के लिए लाभ

फंड मैनेजर्स पर दैनिक रिडेम्पशन और नए निवेश के मानसिक दबाव से मुक्ति मिलेगी। रिडेम्प्शन के दबाव से मुक्त होकर वे बेहतर और दीर्घकालिक रणनीतियों पर काम कर पाएंगे, जिससे उनके निवेश निर्णय बेहतर होंगे।

कार्यान्वयन का प्रस्तावित मॉडल

म्यूचुअल फंड्स को ट्रेडेबल बनाने के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया जा सकता है:-

1. एनएसई का म्यूचुअल फंड सर्विस सिस्टम (एमएफएसएस): एनएसई पहले से ही एमएफएसएस प्रदान करता है, इसी प्रकार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीएसई स्टार, जिसके माध्यम से निवेशक म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद और बेच सकते हैं। इस प्रणाली को विस्तारित करके सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए अनिवार्य किया जा सकता है।

2. डेली एनएवी के आधार पर ट्रेडिंग: जैसे आरबीआई हर दिन विदेशी मुद्राओं के लिए रेट तय करता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनियां हर शाम अपनी एनएवी घोषित करती हैं। इसी एनएवी के आधार पर अगले दिन की ट्रेडिंग हो सकती है।

3. डिपॉजिटरी सिस्टम का उपयोग: एनएसडीएल और सीएसडीएल जैसे डिपॉजिटरीज पहले से ही म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डीमैट फॉर्म में रखने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस व्यवस्था को अनिवार्य बनाया जा सकता है।

सरकार और सेबी से अपेक्षा

जब सेबी ने लिस्टेड सिक्योरिटीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए डीमैट फॉर्मेट अनिवार्य कर दिया है, तो समय आ गया है कि सरकार और सेबी सभी स्टेकहोल्डर्स से चर्चा कर इस महत्वपूर्ण सुधार को लागू करें। म्यूचुअल फंड्स को अनिवार्य डीमैट फॉर्मेट में लाकर भारत के शेयर बाजार को पारदर्शिता, तरलता और निवेशकों के विश्वास का नया आधार दिया जाए। यह न केवल निवेशकों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि पूरे वित्तीय बाजार के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। सरकार और सेबी को सभी हितधारकों - एसेट मैनेजमेंट कंपनियों, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज और निवेशकों - के साथ मिलकर इस परिवर्तन को लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए। यह कदम भारतीय वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता, कुशलता और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा, जिससे अंततः निवेशकों का कल्याण होगा। भारत के वित्तीय बाजारों में यह परिवर्तन एक नए जीवन, नए युग और नई दिशा की शुरुआत होगी, जो हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल
चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
जयपुर।

राशिफल शनिवार 21 जून, 2025

पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, अश्विनी नक्षत्र सायं 7:50 तक, अतिगंड योग रात्रि 8:29 तक, विष्टिकरण प्रातः 7:19 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मेष, मंगल-सिंह, बुध-मिथुन, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज भद्रा प्रातः 7:19 तक है। सायन कर्क में सूर्य प्रवेश प्रातः 8:12 पर होगा। आज योगिनी एकादशी व्रत स्मार्तों का है। आज एकादशी तिथि का क्षय हुआ है। आज सूर्य दक्षिणायन आरम्भ होगा। वर्षा ऋतु आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:20 से 9:03 तक, चर 12:38 से 2:11 तक, लाभ-अमृत 2:11 से 5:36 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:19

मेष

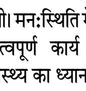

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृष

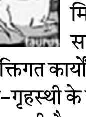

मित्रों-रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है। व्यक्तिगत कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।

मिथुन

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क

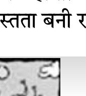

व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह

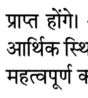

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

तुला

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

वृश्चिक

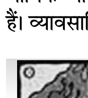

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

धनु

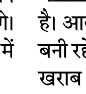

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर

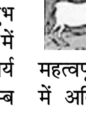

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

मीन

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।